



Thu 03 Sep - 2026

Year - 01

Issue - 160

Page - 01

Rs. - 5

www.azadvaani.com

कर्मचारी यूनियनों की मांगों के
समाधान में तेजी के निर्देश:
हरपाल सिंह चीमा



चंडीगढ़, 3 सितंबर 2026: पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारी मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों और समस्याओं को विस्तार से सुना। उन्होंने संबंधित विभागों को कर्मचारियों की उचित मांगों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

चीमा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों से संबंधित उचित मांगों के प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट उप-समिति के समक्ष भेजे जाएं। उन्होंने विशेष रूप से वित्तीय मामलों से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर वित्त विभाग को भेजने को कहा, ताकि आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जा सके।

अमृतसर में अवैध हथियार
नेटवर्क का पर्दाफाश



चंडीगढ़/अमृतसर, 3 सितंबर: पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियार आपूर्ति नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से .30 बोर की 8 अवैध पिस्तौल और 103 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रणजीत सिंह उर्फ जीता (24), निवासी तरनतारन और गुरबीर सिंह उर्फ गोरा (32), निवासी तरनतारन के रूप में हुई है। रणजीत के खिलाफ पहले से शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।

डीजीपी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया एप्लिकेशन के माध्यम से विदेशी हथियार तस्करों के संपर्क में थे और विदेश से अवैध हथियारों की खेप हासिल कर पंजाब में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।

सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इनोवेशन लैब से तकनीकी शिक्षा को नई दिशा: हरजोत सिंह बैस



चंडीगढ़/साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 03 सितंबर 2026: पंजाब सरकार ने तकनीकी शिक्षा को आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के पांच सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इनोवेशन लैब स्थापित की है। तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हरजोत सिंह बैस ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, खुनिमाजरा, खरड में सांसद मलविंदर सिंह कंग की मौजूदगी में इनोवेशन लैब का राज्यस्तरीय उद्घाटन किया।

'पंजाब शिक्षा क्रांति' के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक कक्षा शिक्षा तक सीमित न रखते हुए उन्हें प्रयोग, नवाचार, प्रोटोटाइपिंग और व्यावहारिक तकनीकी कौशल के अवसर उपलब्ध करवाना है। यह परियोजना विभा इंडिया और मेकर भवन फाउंडेशन के सहयोग से लागू की गई है।

करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से खुनिमाजरा, बठिंडा, फिरोजपुर, बडबर और तलवाड़ा के सरकारी

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ये लैब स्थापित की गई हैं। आधुनिक उपकरणों और तकनीक से लैस ये केंद्र विद्यार्थियों को अपने विचारों को प्रोटोटाइप और वास्तविक समाधानों में बदलने के लिए 'मेकर स्पेस' उपलब्ध करवाएंगे।

मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब के पॉलिटेक्निक विद्यार्थी राज्य के भविष्य के तकनीकी कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन लैब के माध्यम से रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, सहयोग, तकनीकी दक्षता और 21वीं सदी के आवश्यक कौशल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विद्यार्थियों को उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी तकनीकी संस्थानों को नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास के आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है। उन्होंने बताया कि पंजाब के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में पहली बार

एयर होस्टेस कोर्स भी शुरू किए गए हैं और सरकारी तकनीकी संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हुई है।

सांसद मलविंदर सिंह कंग ने शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीक, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवंत सिंह मान सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, उत्कृष्टता-आधारित और रोजगारोन्मुख शिक्षा में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इन इनोवेशन लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी विषयों में प्रोजेक्ट आधारित सीखने का अवसर मिलेगा। वे नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान विकसित कर सकेंगे। इससे उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा तथा भविष्य में स्टार्टअप और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

कर्मचारियों को केंद्र के बराबर वेतन-डीए देने को तैयार पंजाब सरकार: हरपाल चीमा

चंडीगढ़, 3 सितंबर 2026: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल डीए की दर बराबर करने के बजाय जरूरत पड़ने पर संपूर्ण वेतन संरचना को केंद्र के अनुरूप करने पर भी विचार कर सकती है।

चीमा ने कहा कि पंजाब अपने राजस्व का करीब 51 प्रतिशत वेतन और पेंशन पर खर्च करता है, जबकि देश का औसत लगभग 38 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य को 1,11,740 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई, जिनमें से 57,177.9 करोड़ रुपये वेतन और पेंशन पर खर्च किए गए।

उन्होंने कहा कि पंजाब के कई प्रमुख वर्गों के कर्मचारियों का मूल वेतन और डीए जोड़कर कुल वेतन केंद्र तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के समकक्ष कर्मचारियों से अधिक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने नवंबर 2021 में 28 प्रतिशत डीए को बढ़ाकर नवंबर 2024 तक 42 प्रतिशत किया, यानी तीन चरणों में 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के समय 2016-21 की अवधि से संबंधित करीब 14,100 करोड़ रुपये का डीए बकाया विरासत में मिला। भगवंत मान सरकार ने इसमें से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4,500 करोड़ रुपये

से अधिक का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शेष बकाये का भुगतान भी वित्तीय क्षमता के अनुसार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि डीए को 60 प्रतिशत करने से राज्य के खजाने पर लगभग 6,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का संतुलन भी बनाए रखना है।

अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने योग्यता के आधार पर 70,900 सरकारी नौकरियों दी हैं और आउटसोर्सिंग आधारित शोषणकारी भर्ती व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कर्मचारी संगठनों से राजनीतिक दबाव के बजाय सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से लंबित मुद्दों का समाधान निकालने की अपील की।

सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब में कर्मचारियों के वेतन और डीए का निर्धारण पंजाब सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2021 के तहत होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के लिए केंद्र सरकार की डीए दर को स्वतः लागू करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी कल्याण, वित्तीय स्थिरता और पंजाब के लोगों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन मंत्रियों ने कहा कि डीए के मुद्दे को केवल प्रतिशत के आधार पर देखने के बजाय कर्मचारियों के कुल वेतन, पेंशन और राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि पंजाब पहले ही अपने सीमित राजस्व का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रहा है, इसलिए किसी भी अतिरिक्त वित्तीय दायित्व का आकलन व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के वैध अधिकारों और बकाये को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विरासत में मिले डीए बकाये से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान शुरू किया है।



पंजाब को तकनीकी शिक्षा में
नंबर-1 बनाने का लक्ष्य, उद्योग-
अकादमिक साझेदारी पर जोर



चंडीगढ़, 3 सितंबर: पंजाब सरकार ने तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में क्षेत्रीय उद्योग-अकादमिक सम्मेलन आयोजित किया। पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण बोर्ड (PSBTE&IT) द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रमुख उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच पर लाकर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, इंटरशिप, प्लेसमेंट और आधुनिक प्रयोगशालाओं पर चर्चा की गई।

तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 27वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और अब राज्य को देश में नंबर-1 बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक संस्थानों को पारंपरिक शिक्षा केंद्रों से बदलकर रोजगारोन्मुखी और नवाचार आधारित संस्थान बना रही है।

बैस ने कहा कि लंबे समय से शिक्षा और उद्योग की जरूरतों के बीच अंतर रहा है। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय आधुनिक मशीनरी, तकनीक और वास्तविक औद्योगिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए पाठ्यक्रम में उद्योगों की भागीदारी, अनिवार्य इंटरशिप, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और लाइव प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के लिए पूरे सेमेस्टर की इंटरशिप तथा फैकल्टी के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आधुनिक मशीनरी से अपग्रेड किया जा रहा है। आई.आई.एम. अहमदाबाद, आई.आई.एम. अमृतसर, आई.आई.टी. रोपड़ और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से फैकल्टी एवं संस्थागत नेतृत्व को भी मजबूत किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि खुनिमाजरा, बठिंडा, फिरोजपुर, बडबर और तलवाड़ा के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अत्याधुनिक इनोवेशन लैब स्थापित की गई हैं। इन लैब में विद्यार्थी प्रोटोटाइप तैयार करने, नई तकनीकों का प्रयोग करने और वास्तविक समस्याओं के समाधान विकसित करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि ये संस्थान भविष्य में पंजाब के तकनीकी नवाचार के महत्वपूर्ण केंद्र बनेंगे।

Innovation & Excellence

Advertisement

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: **+91-90414-88440**

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015